Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश

नवंबर (संग्रह)

2022

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तर प्रदेश **3**

- रानीपुर टाइगर रिज़र्व 3
- उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में गठित होंगी सिविल डिफेंस की इकाई 3
- लखनऊ, कानपुर, अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश के छह शहरों में शुरू होगी आवासीय योजनाएँ 4
- प्रदेश में आईटी सेक्टर में 7 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को कैबिनेट की मंज़ूरी 5
- उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनाने का प्लान तैयार 6
- गोरखपुर के उमा सिंह ने माउंट फ्रेंडशिप पर साइकिल से की चढ़ाई 6
- कतर्निया घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर के रूप में होगा विकसित 7
- गोरखपुर में 474 करोड़ की लागत से गोड़धोइया नाला व रामगढ़ ताल का होगा जीर्णोद्धार 7
- अयोध्या-चित्रकूट धाम मार्ग से सीधे जुड़ेगा सीताकुंड धाम 8
- शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को मिली मंज़ूरी 8
- मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रुद्राक्ष से बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने के दिये निर्देश 9
- उत्तर प्रदेश घटनाक्रम 9
- उत्तर प्रदेश में होगी 'लखपति महिला कार्यक्रम' की शुरुआत 10
- लखनऊ समेत कानपुर नगर व वाराणसी के पूरे क्षेत्र में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू 10
- उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों ने एंज़ाइम से तैयार होने वाले कपड़ों की नई तकनीक खोजी 11
- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 11
- उत्तर प्रदेश में नई पर्यटन नीति-2022 को मिली मंज़ूरी 12
- प्रदेश के 10 ज़िलों में बनेंगे भव्य, अत्याधुनिक न्यायालय 13
- उत्तर प्रदेश के प्रमुख खाद्य उत्पादों को जीआई टैग जल्द 14
- सोनौली में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा लैंडपोर्ट 15
- उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में बनेगा डाटा सेंटर 15
- 'उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023' 15
- उत्तर प्रदेश के शहरों में लागू होगा इंदौर का SWM मॉडल 16
- गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित होगा इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर 17
- एमएनएनआईटी ने बनाई भारत की पहली मानव रहित कार 17
- मुख्यमंत्री ने रामनगरी अयोध्या में 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया 17
- वाराणसी एयरपोर्ट पर जल्द शुरू होगी डिजी यात्रा 18

नोट :

उत्तर प्रदेश

रानीपुर टाइगर रिज़र्व

चर्चा में क्यों ?

31 अक्टूबर, 2022 को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट के माध्यम से बताया कि उत्तर प्रदेश में एक और टाइगर रिज़र्व रानीपुर टाइगर रिज़र्व भारत का 53वाँ बाघ रिज़र्व बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में यह रिज़र्व चित्रकूट ज़िले के रानीपुर में स्थित है, जो 36 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला है। 230.32 वर्ग किमी. कोर क्षेत्र और 299.05 वर्ग किमी. बफर क्षेत्र वाला यह टाइगर रिज़र्व बाघ संरक्षण की कोशिशों को मजबूत करेगा। इसके अलावा करीब 300 वर्ग किमी. का क्षेत्रफल इसमें और जोड़ा जा रहा है।
- इससे राज्य में बाघों की संख्या में भी वृद्धि होगी, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र में इको पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास होगा तथा इसके अलावा प्राकृतिक वातावरण को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखा जा सकेगा। इस टाइगर रिजर्व से बुंदेलखंड में स्थानीय जनता को रोज़गार के नए अवसर भी मिलेंगे।
- उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश स्थित पन्ना टाइगर रिज़र्व से महज 150 किमी. की दूरी पर स्थित है। इस रिज़र्व में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चित्तीदार हिरण, चिंकारा और कई पक्षी और सरीसृप पाए जाते हैं।
- विदित है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद यह राज्य का चौथा टाइगर रिज़र्व है तथा भारत में बाघों की हालिया गिनती 2018 में की गई थी, जिसके मुताबिक देश में 2967 बाघ हैं और इनमें से 173 उत्तर प्रदेश में हैं।
- उल्लेखनीय है कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पिछले महीने रानीपुर टाइगर रिज़र्व को विकसित करने की मंजूरी मिली थी। इस बैठक में बताया गया था कि केन-बेतवा लिंक परियोजना के फलस्वरूप मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिज़र्व में जलभराव होने के कारण यहाँ के बाघ चित्रकूट की ओर आएंगे, जिस कारण सरकार यहाँ टाइगर रिज़र्व बनाने जा रही है।
- भूपेंद्र यादव ने बताया कि रानीपुर टाइगर रिज़र्व अधिसूचित होने के बाद भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर का यह हिस्सा हो गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार कुछ मदों में 60 प्रतिशत व राज्य सरकार 40 प्रतिशत धनराशि देगी। अन्य मदों में केंद्र व राज्य सरकार 50-50 प्रतिशत धनराशि प्रदान करेंगी।

उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में गठित होंगी सिविल डिफेंस की इकाई

चर्चा में क्यों ?

1 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग और कारागार विभाग की समीक्षा करते हुए निर्देश दिये कि प्रदेश के हर ज़िले में सिविल डिफेंस इकाइयाँ गठित की जाएंगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने बताया कि समाज में शांति, सौहार्द और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में नागरिक सुरक्षा विभाग की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है और इसी कारण से सिविल डिफेंस के महत्त्व और उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए इसे प्रदेश के सभी 75 ज़िलों तक विस्तार किया जाएगा।
- ज्ञातव्य है कि वर्तमान में प्रदेश के 27 ज़िलों में नागरिक सुरक्षा इकाइयाँ गठित हैं।

नोट :

- अग्निशमन विभाग, नागरिक सुरक्षा विभाग और कारागार विभाग की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिये कि प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को आधार मानकर नागरिक सुरक्षा इकाइयों का पुनर्गठन किया जाए।
- इस प्रकार प्रदेश में साढ़े सात सौ से अधिक नागरिक सुरक्षा इकाइयाँ क्रियाशील हो सकेंगी। नवीन इकाइयों के सुचारु क्रियान्वयन के लिये प्रदेश सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश कैबिनेट ने हाल ही में अपने नई जेल मैन्युअल को अनुमोदित किया है तथा यह जेल सुधारों की ओर महत्त्वपूर्ण प्रयास साबित होगा। कारागारों को सुधार के बेहतर केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिये ठोस प्रयास करना होगा। 'ओपन जेल'और 'हाई सिक्योरिटी जेल'के उदाहरण इस संबंध में उपयोगी हो सकते हैं।
- मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि प्रदेश की सभी जेलों में 14 वर्ष की अवधि से अधिक समय से बंद कैदियों की सूची तैयार कर उपलब्ध कराई जाए तथा सूची में बीमार, नाबालिग और महिला एवं दिव्यांग कैदियों का पृथक् विवरण भी हो।
- उन्होंने कहा बताया कि अग्निशमन विभाग को आपदा प्रबंधन एवं आपात सेवा के रूप में स्थापित करने की ज़रूरत है तथा केंद्र सरकार के मॉडल 'बिल ऑन मेंटेनेंस ऑफ फायर एंड इमरजेंसी सर्विस-2019' की तर्ज़ पर प्रदेश के मॉडल 'फायर एंड इमरजेंसी बिल' को तैयार किया जाना चाहिये।
- उन्होंने बहुमंजिली इमारतों में प्रत्येक दशा में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होने की बात की तथा कहा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस की नीति के अनुरूप भवन स्वामी द्वारा हर छह माह के अंतराल पर सेल्फ सर्टिफिकेशनरी व्यवस्था, भवनों के प्रकार के अनुसार फायर सेफ्टी ऑफिसर का प्रावधान और वार्षिक थर्ड पार्टी ऑडिट की व्यवस्था को लागू किया जाए।
- उन्होंने कहा कि फायर फाइटर्स की सुरक्षा व उच्चस्तरीय अग्निशमन उपकरणों की उपलब्धता के लिये एक विशेष निधि-कोष की स्थापना के प्रयास किया जाए तथा अंतर्विभागीय समन्वय के साथ कन्वर्जेंस के माध्यम से वित्तीय प्रबंधन करते हुए अधिकाधिक शहरों को सेफ सिटी बनाने की कोशिश करनी चाहिए।

लखनऊ, कानपुर, अयोध्या समेत उत्तर प्रदेश के छह शहरों में शुरू होगी आवासीय योजनाएँ

चर्चा में क्यों ?

2 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश की आवास विकास परिषद की बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया कि प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, मथुरा, बरेली और कन्नौज में आवासीय योजनाएँ शुरू की जाएंगी।

प्रमुख बिंदु

- इस बैठक में बताया गया कि लखनऊ, मथुरा और अयोध्या में आवासीय योजना उत्तर प्रदेश दिवस पर 24 जनवरी, 2023 को ही लॉन्च होंगी, जबकि बरेली, कानपुर तथा कन्नौज की योजना भी वर्ष 2023 में ही आएंगी।
- कानपुर की मंधना आवासीय योजना की ज़मीन अब अनिवार्य अभिनिर्णय के तहत ली जाएगी। इसके अलावा लखनऊ में प्रदेश का सबसे बड़ा 5000 क्षमता का कन्वेंशन सेंटर बनेगा तथा अवध विहार और वृंदावन के रिक्त फ्लैटों में 15 प्रतिशत की छूट मिलेगी। आवास विकास परिषद ने लखनऊ, मथुरा, अयोध्या योजना के लिये ज़मीन अधिग्रहित कर ली है।
- अपर आवास आयुक्त एवं सचिव डॉ. नीरज शुक्ला ने बताया कि लखनऊ में 265 एकड़ ज़मीन नई जेल रोड पर ली गई है। इसके अलावा मथुरा में 300 एकड़ में नई आवासीय योजना आएगी।
- अयोध्या योजना के लिये मांझा बरेहटा, माझा सहनवाजपुर व तिहुरा गाँव की पहले 1291 एकड़ ज़मीन ली जा रही थी। अब माझा बरेहटा की 241 एकड़ ज़मीन और लिये जाने का निर्णय हुआ है। वर्तमान में 600 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन का अधिग्रहण हो चुका है।
- उन्होंने बताया कि आवास विकास परिषद की मथुरा आवासीय योजना प्राइम के लिये करीब पौने 300 एकड़ ज़मीन ली जा रही है। इसके एक तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है तथा दूसरी तरफ छटीकरा वृंदावन रोड है। यह योजना वृंदावन के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थित है तथा वृंदावन के मुख्य मंदिरों में से एक माता वैष्णो मंदिर से लगी बाउंड्री पर स्थित है।

नोट :

- बरेली शाहजहाँपुर रोड पर नई आवासीय योजना के लिये 561 हेक्टेयर जमीन ली जा रही है। यह योजना लैंड पूलिंग स्कीम के तहत विकसित होगी।
- कानपुर की मंधना योजना 229 हेक्टेयर में विकसित होगी तथा इस योजना के लिये वर्ष 2009 में धारा 28, यानी अधिग्रहण का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। यहाँ के किसान आपसी सहमति से ज़मीन नहीं दे रहे हैं, इसलिये बोर्ड ने अनिवार्य अभिनिर्णय के तहत यहाँ की ज़मीन लेने का फैसला लिया है।
- 89.52 एकड़ में कन्नौज में भी नई आवासीय योजना लाई जा रही है। इसके लिये धारा 28 का नोटिफिकेशन हो गया है। इसके अंतर्गत मदनपुर बड्ड, यूसुफपुर भगवान सहित चार गाँवों की ज़मीन ली जा रही है।

प्रदेश में आईटी सेक्टर में 7 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को कैबिनेट की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

3 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में आईटी सेक्टर में सात हज़ार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि प्रदेश सरकार आईटी सेक्टर में माइक्रोसॉफ्ट में 2186 करोड़ रुपए का, एमएक्यू में 483 करोड़ रुपए और पेटीएम में 638 करोड़ रुपए का निवेश नोएडा में करेगी तथा इस निवेश के ज़रिये 14185 लोगों को रोज़गार मिलेगा।
- इसके अलावा, प्रदेश में डाटा सेंटर के लिये भी दो निवेश प्रस्तावों को मंज़ूरी मिली, जिनमें एक सिंगापुर की कंपनी एसटीपी नोएडा में डाटा सेंटर के लिये 1130 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जबकि एक अन्य कंपनी एसकेबीआर 2692 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इन दोनों परियोजनाओं के ज़रिये 4 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलेगा।
- कैबिनेट ने डाटा सेंटर नीति में बदलाव करते हुए हाल ही में ग्रेटर नोएडा में खुले उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर के बाद सूबे में 7 और डाटा सेंटर खोलने का फैसला किया है। इन सभी डाटा सेंटर के लिये भूमि अनुदान की व्यवस्था की जाएगी तथा इसके अलावा डुएल फीडर की सप्लाई में एक फीडर की सप्लाई का खर्च वहन भी किया जाएगा।
- अतिरिक्त मुख्य सचिव (आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स) अरविंद कुमार ने बताया कि डाटा सेंटर के लक्ष्य को बढ़ाकर 900 मेगावाट के डाटा सेंटर बनाने का फैसला किया गया है। इसके लिये एफएआर की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है, ताकि नक्शे जल्दी पास हो सकें। इसमें पार्शियल कंप्लीशन की व्यवस्था दी गई है, जबकि बिजली कनेक्शन को लेकर भी सुविधाएँ बढ़ाई गई हैं।
- इसके अलावा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डाटा सेंटर की फील्ड में भी दस करोड़ रुपए तक की फंडिंग की जाएगी। डाटा सेंटर में हुए इन बदलावों से न सिर्फ निवेश बढ़ेगा, बल्कि यह और तेज़ी से भी आएगा। ये पॉलिसी 5 साल तक के लिये मान्य होगी।
- अरविंद कुमार ने बताया कि प्रदेश में तीन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहले ही खोले जा चुके हैं तथा 5 नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और खोले जाएंगे, जिनमें ये सेंटर 3डी प्रिंटिंग, 5जी, वर्चुअल रिएलिटी, स्पेसटेक जैसे नये क्षेत्र में खुलेंगे। स्कूल स्तर पर ही इनोवेटिव कल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा सस्टेनेंस अलाउंस को 15 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 17.5 हज़ार रुपए किया गया है।
- सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रोटोटाइप बनाने के लिये भी अब 5 लाख रुपए का अनुदान मिल सकेगा। ग्रामीण परिवेश को प्रभावित करने वाले, कूड़े को रिसाइकिल करने वाले, पर्यावरण संरक्षण, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर में स्टार्ट-अप शुरू करने वालों को 50 प्रतिशत अधिक इंसेंटिव प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी वाले स्टार्ट-अप की भी परिभाषा तय की गई है, जिसके तहत स्टार्ट-अप में 26 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी होना ज़रूरी है।
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में तीन नए विश्वविद्यालयों को मंज़ूरी भी दी है, जिसमें कर्नाटक का विख्यात जेएसएस विश्वविद्यालय नोएडा में, एसडी सिंह विश्वविद्यालय फतेहगढ़-फर्रुखाबाद में और एसडीजीआई ग्लोबल विश्वविद्यालय गाज़ियाबाद में खोला जाएगा। इन तीनों विश्वविद्यालयों को आशय-पत्र जारी कर दिये गए हैं।

नोट :

उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी बनाने का प्लान तैयार

चर्चा में क्यों ?

6 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रस्ताव को प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके बाद जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये सरकार 2027 तक 40 लाख करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करेगी, जिसके अंतर्गत यह धनराशि बुनियादी ढाँचा, स्वास्थ्य, न्यायिक प्रणाली, शिक्षा, भारी उद्योग आदि पर खर्च होगी।
- सरकार के अनुसार वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था पाने के लिये सालाना विकास दर 30 से 35 प्रतिशत तक बढ़ानी होगी और प्रदेश में हर वर्ष होने वाली जीएसडीपी के निवेश को बढ़ाकर 43 से 47 प्रतिशत करना होगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लक्ष्य को बढ़ाकर वर्तमान का 45 प्रतिशत तक ले जाना होगा, जिससे प्रदेश में अधिक-से-अधिक इकाइयाँ तो लगेंगी ही, साथ में रोज़गार भी बढ़ेगा और प्रदेश की इकॉनमी मज़बूत होगी।
- प्रदेश में निवेशकों को लुभाने के लिये इन्वेस्टमेंट नीति का खाका तैयार किया गया है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और नई इकॉनमी को विभिन्न चरणों में बाँटने के साथ इस पर ज़ोर दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को दो भागों में बाँटा गया है, जिसके हार्ड और सॉफ्ट दो हिस्से हैं। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉजिस्टिक के साथ पावर और एनर्जी शामिल हैं, जबकि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में नियामक, न्यायिक प्रणाली, शिक्षा, स्वास्थ्य को शामिल किया गया है। इसके अलावा सर्विस में पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य को शामिल किया गया है।
- सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत पूरे प्रदेश में आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था के लिये राज्य सरकार को वर्ष 2022 से 2027 के बीच करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे, जिनमें 24 लाख बेड के अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिये करीब 4.35 लाख डॉक्टर्स और 17 लाख नर्स की भर्ती की जाएगी।
- हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत अधीनस्थ न्यायालय में 1092 जज की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा हाईकोर्ट में 90 नए जज की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश में 13 लाख करोड़ रुपए बिजली, 25 लाख करोड़ रुपए रोड और 200 करोड़ रुपए न्यायिक प्रणाली पर खर्च किये जाएंगे।

गोरखपुर के उमा सिंह ने माउंट फ्रेंडशिप पर साइकिल से की चढ़ाई

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के उमा सिंह ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में इतिहास रचते हुए हिमाचल प्रदेश में मनाली स्थित माउंट फ्रेंडशिप की चोटी साइकिल से फतह कर नया रिकॉर्ड बनाया है और इस तरह वे साइकिल से इस पर्वत की चोटी पर पहुँचने वाले पहले पर्वतारोही बन गए हैं।

प्रमुख बिंदु

- विदित है कि गोरखपुर में बांसगांव तहसील क्षेत्र के गोड़सैरा गाँव के रहने वाले उमा सिंह ने 25 अक्टूबर को साइकिल से इस यात्रा की शुरुआत की थी। उन्होंने साइकिल से ही 2 नवंबर को मनाली तक करीब 1400 किमी. का सफर पूरा किया। वहाँ से 2 नवंबर को ही इस अभियान की शुरुआत कर दी। पूरी यात्रा में उन्हें कुल 12 दिन लगे थे।
- 17,346 फीट ऊँचे माउंट फ्रेंडशिप का शीर्ष करीब दो सौ मीटर तक दीवार की तरह खड़ा है। इसलिये वहाँ तक पहुँचना संभव नहीं था। गाइड के निर्देशानुसार टॉप से 200 मीटर नीचे से ही उन्होंने तिरंगा फहराने के बाद वापसी की।
- इससे पहले भी उमा सिंह 15 से 17 जुलाई के बीच कश्मीर से कन्याकुमारी (3629 किमी.) का सफर किराए की स्पोर्ट्स बाइक से रिकॉर्ड 63 घंटे 35 मिनट 20 सेकेंड में तय किया था और 12 से 15 अगस्त के बीच हिमालय पर्वत की चार चोटियों पर साइकिल से चढ़ाई कर पहले भारतीय और दुनिया के तीसरे पर्वतारोही बने थे।

नोट :

- इसके अलावा उन्होंने 15 अगस्त, 2021 को अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊँची चोटी माउंट किलिमंजारो (19340 फीट) पर साइकिल से चढ़ाई कर तिरंगा फहराया था।
- विदित है कि 30 नवंबर, 2020 से 10 फरवरी, 2021 के बीच 73 दिनों में 12,271 किमी. का सफर साइकिल से पूरा करने का रिकॉर्ड उमा के नाम है। इस दौरान उन्होंने देश के सभी राज्यों और उनकी राजधानी तक अपनी दस्तक दी।

कतर्निया घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर के रूप में होगा विकसित

चर्चा में क्यों ?

7 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के डीएफओ आकाशदीप बधावन ने बताया कि कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग में घड़ियाल कंजर्वेशन व रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- इसके लिये 10 सदस्यीय शोध और प्रशिक्षुओं का दल कतर्निया पहुँच गया है। यहाँ तीन महीने रहकर यह दल घड़ियाल पर डाक्यूमेंट्री फिल्म तैयार करेगा।
- जलीय क्षेत्र में घड़ियाल के कुनबों को बढ़ाने व उनके रहन-सहन पर रिसर्च कर शोध-पत्र तैयार किया जाएगा। इसी के आधार पर सरकार पर्यटन स्थल के स्वरूप व घड़ियाल रिसर्च सेंटर तक की योजना को अंतिम रूप देगी।
- गौरतलब है कि भारत-नेपाल सीमा से कतर्नियाघाट वन्यजीव प्रभाग लगा हुआ है। 551 वर्ग किलोमीटर में प्रभाग में बाघ, तेंदुआ, हाथी, गैंडा समेत कई तरह के दुर्लभ वन्यजीव व पक्षियों का बसेरा है। कतर्निया के बीच होकर बहने वाली गेरुआ नदी के छह किलोमीटर के दायरे में घड़ियाल के कुनबों का बसेरा रहता है। देश भर में कतर्नियाघाट घड़ियाल कंजर्वेशन के रूप में ही शुरुआत से जाना जाता है।
- अब इसी पहचान को राष्ट्रीय व विश्व फलक पर चमकाने की तैयारी हो रही है। इसके तहत घड़ियालों के कुनबों को बढ़ाने के साथ ही घड़ियाल सेंटर के आकार को भी बदलने की योजना बन रही है।
- 10 सदस्यीय टीम में तीन शोधकर्त्ता, छह प्रशिक्षु शोधकर्त्ता व एक मूवी मेकर शामिल हैं। यह टीम तीन माह कतर्निया में रहकर शोध करेगी। शोध रिपोर्ट के आधार पर सेंटर का स्वरूप तैयार किया जाएगा।
- कतर्नियाघाट पर फिल्म बनाई जा चुकी है, लेकिन विशेषकर घड़ियाल पर पहली बार डाक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की तैयारी हो रही है। फिल्म में कतर्निया के शोध-पत्रों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि भविष्य में छात्रों को शोधपरक सामग्री आसानी से मिल सके।
- गेरुआ में 12 पूल बने हुए हैं। इनमें से तीन पूल में कछुआ का बसेरा है, जबकि एक पर मगरमच्छों का कब्ज़ा है। वहीं छह पूलों में घड़ियालों का कुनबा रहता है। जिस तेजी से इनकी संख्या बढ़ रही है, ऐसे में पूल कम और आकार में छोटे पड़ रहे हैं। बड़े घड़ियाल चार से पाँच फूट के होते हैं। एक पूल में छह से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं।
- डीएफओ ने बताया कि वाइल्ड लाइफ से दशकों से जुड़ी मूवी मेकिंग की बंगलूरू की विशेषज्ञ त्रिशाला अशोक भी टीम के साथ आई हुई हैं। रिसर्च में कॉलेज के छात्रों को भी जोड़ा जाएगा। इसमें मूवी मेकिंग में रुचि रखने वाले छात्रों को विशेषज्ञ जानकारी साझा कर उनकी जिज्ञासा बढ़ाएंगी।

गोरखपुर में 474 करोड़ की लागत से गोड़धोइया नाला व रामगढ़ ताल का होगा जीर्णोद्धार

चर्चा में क्यों ?

7 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 474.42 करोड़ रुपए की गोड़धोइया नाले और रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार तथा 561.34 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना ज़ोन सी पार्ट-दो, योजनाओं को मंज़ूरी दी।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि गोरखपुर सिटी में गोड़धोइया नाला पहले एक प्राकृतिक नाला था, जिसके आसपास के क्षेत्रों में शहरीकरण के कारण विभिन्न नाले के माध्यम से सीवेज युक्त गंदा पानी गिरने और अतिक्रमण से सिल्ट भर गई है। इसी कारण से यहाँ के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

नोट :

- इसको ध्यान में रखते हुए गोड़धोइया नाला और रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार व इंटरसेप्शन डयवर्जन एवं ट्रीटमेंट की परियोजना तैयार की गई है। परियोजना के अंतर्गत 44300 घरों से निकलने वाले 38 एमएलडी सीवरेज का ट्रीटमेंट किया जाएगा।
- इसमें नाले के दोनों तरफ आरसीसी रिटेनिंग वाल बनाई जाएगी तथा इसके दोनों तरफ सीवरेज लाइन डाली जाएगी। इसके पास में ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा और बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जाएगा।
- इस परियोजना से गोड़धोइया नाले के 9.7 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले करीब 2.2 लाख परिवारों को बाढ़ और जल जनित बीमारियों से राहत मिलेगी। इसके अलावा वर्ष 2025 की जनसंख्या की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सुविधा विकसित की जाएगी। इस पर 561.34 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसमें सीवरेज लाइन डालते हुए 43963 घरों में कनेक्शन भी दिया जाएगा।

अयोध्या-चित्रकूट धाम मार्ग से सीधे जुड़ेगा सीताकुंड धाम

चर्चा में क्यों ?

8 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता संतोष मणि तिवारी ने बताया कि राज्य के सुल्तानपुर में आदिगंगा गोमती तट पर स्थित सीताकुंड घाट को सीधे अयोध्या-प्रयागराज-चित्रकूट धाम मार्ग से जोड़ा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- संतोष मणि तिवारी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग पर जाम को कम करने व यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये द्वारिकागंज व टाटियानगर से शहर के अंदर आने वाले दो लिंक हाईवे को फोरलेन में तब्दील करने की योजना है। योजना में से द्वारिकागंज से गोलाघाट तक 10 किमी. की दूरी को शामिल किया गया है तथा इसके अलावा टाटियानगर से रतनपुर टेंढुई तक को भी शामिल किया गया है।
- गोलाघाट से द्वारिकागंज तक 10 किमी. दूरी में फोरलेन निर्माण के लिये 50 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है, जिसमें कई पुल व पुलिया को भी शामिल किया गया है।
- अयोध्या-चित्रकूट धाम मार्ग से सीताकुंड धाम को जोड़ने को लेकर इस लिंक हाईवे फोरलेन का निर्माण होगा। इस मार्ग की चौड़ाई शहर के अंदर 50 फीट और शहर के बाहर सड़क के मध्य से 75 फीट होगी और निर्धारित सीमा के अंदर कब्जेदारों को मुआवज़ा भी नहीं मिलेगा।
- टाटियानगर से टेंढुई तक लगभग तीन किमी. की दूरी के लिये 10 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। इसमें भी एक पुल और कई पुलिया को शामिल किया गया है। शासन की मांग पर लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड ने स्टीमेट भी तैयार किया है।

शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

9 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि नेशनल हेल्थ मिशन ने शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के संचालन को मंज़ूरी प्रदान कर दी है। इसके तहत बच्चों की जन्मजात बीमारियों की पहचान कर उनका इलाज किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने बताया कि पहले चरण में प्रदेश के 15 ज़िलों में योजना लागू की जाएगी। दूसरे चरण में 16 और ज़िलों को शामिल किया जाएगा।
- पहले चरण के तहत वर्ष 2020-21 में आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू किया जाएगा।
- 15 ज़िलों में कुल 40 मोबाइल हेल्थ टीम रखी जाएंगी। प्रत्येक टीम में चार सदस्य होंगे। जिसमें एक महिला व एक पुरुष आयुष चिकित्सक होंगे। संविदा पर करीब 60 डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती होगी।

नोट :

- दूसरे चरण में 2022-2023 में आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, बुलंदशहर, चंदौली, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हाथरस, जालौन, कुशीनगर, मथुरा, मिर्जापुर, रामपुर, शाहजहाँपुर व सीतापुर में बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि आरबीएसके के तहत चाइल्ड हेल्थ स्क्रीनिंग और अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज में स्क्रीनिंग की जाती है, जिसमें कटे होंठ, तालू, तंत्रिका ट्यूब दोष, डाउन सिंड्रोम, एनीमिया, विटामिन ए-डी की कमी, कुपोषण, जन्मजात मोतियाबिंद व दिल समेत दूसरी बीमारियों की पहचान की जाती है।
- कार्यक्रम के तहत 18 साल तक के बच्चों में तय बीमारियों की पहचान कर इलाज मुहैया कराया जाता है। योजना के तहत मोबाइल हेल्थ टीम चिह्नित स्थानों पर जाकर बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच करेंगी। बीमारी की दशा में उच्च सरकारी संस्थानों में इलाज के लिये रेफर किया जाएगा ताकि समय पर इलाज मिल सके।

मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में रुद्राक्ष से बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने के दिये निर्देश

चर्चा में क्यों ?

10 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के गोरखपुर में एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनाने का निर्देश दिया है, जिसकी सीट क्षमता तीन हज़ार से पाँच हज़ार के बीच होगी।

प्रमुख बिंदु

- गोरखपुर में बनने वाले कन्वेंशन सेंटर की क्षमता वाराणसी में बने हुए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की क्षमता (1200) से ज़्यादा होगी।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि गोरखपुर का कन्वेंशन सेंटर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त ऐसा कन्वेंशन सेंटर होगा, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजन हो सकेंगे। इसके लिये गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने ज़मीन की तलाश भी शुरू कर दी है।
- गोरखपुर में इस कन्वेंशन सेंटर के बनने से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार, प्रदर्शनी व अन्य सार्वजनिक आयोजन आसानी से हो सकेंगे।
- कला, संस्कृति, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कन्वेंशन सेंटर एक हब का काम कर सकता है। इस कन्वेंशन सेंटर को वैवाहिक कार्यक्रम के लिये भी किराये पर दिया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश घटनाक्रम

चर्चा में क्यों ?

9 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (खेल) नवनीत सहगल ने बताया कि देश में अप्रैल 2023 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में होंगे।

प्रमुख बिंदु

- नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन प्रदेश के चार शहरों लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी तथा नोएडा में होगा। इसमें रोईंग, बास्केटबाल, जूडो, कबड्डी, कुश्ती, स्वीमिंग, बॉक्सिंग सहित लगभग 20 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।
- इन खेलों में पूरे देश से लगभग 150 यूनिवर्सिटी के करीब 4,500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में अंडर-26 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वूमेन गेम्स पर विशेष फोकस रहेगा।
- नोएडा में कबड्डी, जूडो, आर्चरी तथा फेंसिंग का आयोजन होगा। गोरखपुर में रोईंग और वाराणसी में रेसलिंग, मलखंब तथा योगा से संबंधित खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित कराई जाएंगी। अन्य प्रतियोगिताएँ राजधानी लखनऊ में होंगी।
- अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल के मुताबिक यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन से विश्वविद्यालयों में खेल का माहौल बनेगा और यहाँ के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन से प्रदेश में खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा।

नोट :

- गौरतलब है कि यह आयोजन खेल मंत्रालय से उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, ऐसे में भारतीय खेल प्राधिकरण के दिल्ली में स्थित खेलो इंडिया मुख्यालय की भी यूनिवर्सिटी गेम्स में अहम भूमिका रहेगी।
- इससे पहले यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण ओडिशा (2020) और दूसरा संस्करण कर्नाटक (2021) में हो चुका है। कर्नाटक में आयोजित 20 स्पर्धाओं में देश भर से 190 यूनिवर्सिटी के साढ़े चार हज़ार खिलाड़ी शामिल हुए थे।

उत्तर प्रदेश में होगी 'लखपति महिला कार्यक्रम' की शुरुआत

चर्चा में क्यों ?

13 नवंबर, 2022 को मीडिया जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से और सक्षम बनाने के लिये 'लखपति महिला कार्यक्रम' शुरू करने जा रही है, जिसके ज़रिये शुरुआती तीन वर्षों में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में 'लखपति महिला कार्यक्रम'के ज़रिये ऐसे प्रयास किये जाएंगे कि महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से अधिक पहुँचाई जा सके। इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपी गई है और इस कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र के सामने प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है,जिसको मिशन मोड में लागू कर जल्द ही नतीजे हासिल किये जाने की योजना है।
- लखपति महिला कार्यक्रम'के पहले चरण में 11 ज़िलों में इसकी शुरुआत की जाएगी,जिसमें वाराणसी और प्रयागराज के अलावा अलीगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, बांदा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, हमीरपुर और सोनभद्र शामिल हैं। इन ज़िलों में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जोड़कर वार्षिक आय में बढ़ोतरी का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
- इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द नतीजे तक पहुँचाने के लिये समय सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके तहत ज़िला और विकासखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 15 नवंबर तक ज़िला और विकासखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन हो जाएगा और 30 मार्च के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।
- टास्क फोर्स के अध्यक्ष ज़िला स्तर पर वहाँ के ज़िलाधिकारी होंगे, जबकि मुख्य विकास अधिकारी सचिव होंगे। उपायुक्त स्वत: रोज़गार, उपायुक्त मनरेगा इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा कृषि विकास, बागवानी, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन के सदस्य भी इस टास्क फोर्स में शामिल होंगे।
- इस टास्क फोर्स की कार्य प्रगति की मासिक समीक्षा करनी होगी। टास्क फोर्स का कार्य लखपति महिला एप पर विकास खंड के सभी स्वयं सहायता समूह की सदस्यों की स्वघोषित आय को अपलोड करने एवं मनरेगा में सम्मिलित निजी एवं सामूहिक आजीविका संवर्धन योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करनी होगी।

लखनऊ समेत कानपुर नगर व वाराणसी के पूरे क्षेत्र में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू

चर्चा में क्यों ?

14 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश डीजीपी मुख्यालय ने लखनऊ, कानपुर नगर और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के पुनर्गठन को मंज़ूरी दे दी। कानपुर नगर और वाराणसी में एक-एक ज़ोन बढ़ाया गया है, जबकि लखनऊ ग्रामीण के थानों को लखनऊ में समायोजित कर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

- एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि तीनों ही ज़िलों में कमिश्नरेट के पहले के ढाँचे में बदलाव किया गया है। अब लखनऊ में 52 थाने, 16 सर्किल और पाँच ज़ोन होंगे। कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट में 49 थाने, 14 सर्किल और चार ज़ोन होंगे। वहीं वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में 30 थाने, 9 सर्किल और तीन ज़ोन होंगे।

नोट :

- कानपुर में सेंट्रल और वाराणसी में गोमती नया ज़ोन बनाया गया है। कानपुर में एक डीसीपी, एक एडीसीपी और चार एसीपी का पद बढ़ाया गया है। इसी तरह वाराणसी में एक डीसीपी, एक एडीसीपी और तीन एसीपी का पद बढ़ा है।
- लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में कोई नया ज़ोन नहीं बनाया गया है। ग्रामीण के सात थानों को अलग-अलग ज़ोन में शामिल कर दिया गया है। हालाँकि, लखनऊ में तीन एसीपी का पद बढ़ाया गया है।
- वाराणसी में गोमती नया ज़ोन होगा। इसके साथ ही वाराणसी में अब ज़ोन की संख्या दो से बढ़कर तीन हो गई है। सर्किल की संख्या भी छह से बढ़कर नौ हो गई है। काशी ज़ोन में 13 थाने, वरुणा ज़ोन में 10 थाने और गोमती ज़ोन में सात थाने रखे गए हैं। काशी ज़ोन में चार सर्किल, वाराणसी ज़ोन में तीन सर्किल और गोमती ज़ोन में दो सर्किल रहेंगे।

उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिकों ने एंज़ाइम से तैयार होने वाले कपड़ों की नई तकनीक खोजी

चर्चा में क्यों ?

16 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान विभाग के निदेशक डॉ. जी नलन किल्ली ने बताया कि विभाग के वैज्ञानिक प्रो. एके पात्रा ने मनपसंद रंग और डिज़ाइन के कपड़े रसायान की बजाय एंज़ाइम से तैयार करने की एक नई तकनीक खोजी है। लैब में इसका सफल प्रयोग भी हो चुका है।

प्रमुख बिंदु

- प्रो. पात्रा ने बताया कि एंज़ाइम की तकनीक से बने कपड़े मानव शरीर और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। इसमें पर्यावरण के मित्र इंज़ाइम को विभिन्न केमिकल के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
- उन्होंने बताया कि कपड़ा खराब होने या फटने पर फेंकने की स्थिति में यह एंज़ाइम मिट्टी में मिलकर उसे उर्वर बनाएगा। यह एंज़ाइम पानी या मानव शरीर को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा।
- विदित है कि कानपुर के वैज्ञानिक प्रो. पात्रा उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान में टेक्सटाइल केमिस्ट्री विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। इन्होंने 800 से अधिक ऐसे केमिकल सूचीबद्ध किये हैं, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में प्रयोग किये जाते हैं और जो पर्यावरण के लिये हानिकारक हैं। उनका यह रिसर्च पेपर इंग्लैंड के प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित किया गया है।
- वस्त्रों को रसायनों से बचाने की तकनीक खोजने समेत ऐसे कार्यों के लिये प्रो. पात्रा को दुनिया के सर्वोच्च टेक्सटाइल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। यह अवार्ड उन्हें इंग्लैंड की 'द सोसायटी ऑफ डायर एंड कलरिस्ट'की ओर से दिया जाएगा। प्रो. पात्रा चार्टर्ड कलरिस्ट अवार्ड पाने वाले देश के पहले वैज्ञानिक होंगे।
- उल्लेखनीय है कि चार्टर्ड कलरिस्ट अवार्ड टेक्सटाइल में शोध व एकेडमिक क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर दिया जाता है।

उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022

चर्चा में क्यों ?

16 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 को मंज़ूरी दी गई, जिसमें सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिये कई अहम प्रावधान किये गए हैं। यह नीति पाँच वर्ष तक लागू रहेगी।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 के क्रियान्वयन के लिये उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा) को नोडल एजेंसी नामित किया गया है।
- इस नीति के अंतर्गत सोलर पावर प्लांट की स्थापना के लिये सरकारी उपक्रमों को एक रुपए प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से ग्राम पंचायत व राजस्व भूमि दी जाएगी। निजी क्षेत्र में सोलर पार्क की स्थापना के लिये 15 हज़ार रुपए प्रति एकड़ प्रतिवर्ष की दर से 30 वर्ष के लिये पट्टे पर दी जाएगी।

नोट :

- राज्य सरकार ने अगले पाँच वर्ष में सौर ऊर्जा से 22 हज़ार मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। सोलर पार्क से 14,000 मेगावाट, सोलर रूफटॉप आवासीय से 4500 मेगावाट, सोलर रूफटॉप अनावासीय से 1500 मेगावाट तथा पीएम कुसुम योजना के तहत 2000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।
- उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने निजी आवासों पर नेट मीटरिंग व्यवस्था के साथ ग्रिड संयोजित सोलर सिस्टम की स्थापना पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के अलावा राज्य सरकार की ओर से 15 हज़ार रुपए प्रति किलोवॉट, अधिकतम 30,000 रुपए प्रति उपभोक्ता के राज्य अनुदान की अनुमन्यता को भी स्वीकृति दी है।
- सरकारी और शिक्षण संस्थानों के भवनों पर नेट मीटरिंग के साथ सोलर रूफटॉप अनुमन्य किया गया है। पीएम कुसुम योजना के तहत भी किसानों के लिये सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।
- कैबिनेट ने सौर ऊर्जा इकाइयों की स्थापना के लिये खरीदी अथवा लीज पर ली जाने वाली जमीन देय स्टांप शुल्क में शत प्रतिशत छूट देने के साथ ही इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 10 वर्ष के लिये छूट प्रदान किये जाने की अनुमति दी है।
- सौर प्लांट को पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करने से छूट प्रदान करने, ग्रिड संयोजित सोलर पीवी परियोजनाओं को प्रदूषण नियंत्रण नियम के तहत स्थापना और संचालन की सहमति व एनओसी प्राप्त करने से छूट देने का निर्णय किया गया है।
- इस नीति के क्रियान्वयन के लिये उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा) को नोडल एजेंसी नामित किया गया है।
- इस नीति के अनुसार पाँच मेगावाट अथवा उससे अधिक क्षमता के स्टोरेज सिस्टम के साथ स्थापित सोलर पार्कों को ढाई करोड़ रुपए प्रति मेगावाट की दर से सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी।
- इस नीति के तहत अयोध्या शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के 16 नगर निगमों तथा नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा।
- इसके तहत संबंधित शहर की पारंपरिक ऊर्जा की अनुमानित कुल मांग की न्यूनतम 10 प्रतिशत बिजली शहर क्षेत्र में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों से पूरी की जाएगी।
- इसके लिये नीति के अंतर्गत 2011 की नगर निगम क्षेत्र की जनगणना के अनुसार 100 रुपए प्रति व्यक्ति की दर से राज्य सरकार द्वारा नगर निगमों/नोएडा सिटी को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिये वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- सौर ऊर्जा संयंत्रों की रख-रखाव के लिये अतिरिक्त जनशक्ति का सृजन किया जाएगा। इसके लिये 30,000 युवकों को सौर ऊर्जा संयंत्रों के अनुरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें 'सूर्य मित्र'का नाम दिया जाएगा। इस तरह इन 'सूर्य मित्रों'के लिये रोज़गार भी सृजित होगा।

उत्तर प्रदेश में नई पर्यटन नीति-2022 को मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

16 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता से हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की नई पर्यटन नीति-2022 को मंज़ूरी मिली।

प्रमुख बिंदु

- राज्य की नई पर्यटन नीति में होटल इंडस्ट्री के लिये निवेश आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 2 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 40 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। इसमें होटलों को उद्योग का दर्जा मिलेगा तथा पानी, बिजली संपत्ति कर, सीवरेज टैक्स की दरें भी व्यवसायिक की जगह औद्योगिक होंगी।
- नई पर्यटन नीति के अंतर्गत भगवान राम से जुड़े सभी स्थलों को रामायण सर्किट, भगवान कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को कृष्ण सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा। जिन नए पर्यटन गंतव्यों का विकास किया जाएगा, इसमें रामायण सर्किट प्रमुख होगा।
- रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर समेत अन्य धार्मिक स्थल शामिल होंगे। इन स्थलों को भगवान राम एवं माता सीता के प्रतीकों के तौर पर देखा जाता है।

नोट :

- इसी तरह कृष्ण सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगाँव, बलदेव से लेकर अन्य धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा तथा बुद्धिस्ट सर्किट में कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशांबी, श्रावस्ती, रामग्राम समेत अन्य स्थल शामिल होंगे।
- नई नीति में महाभारत सर्किट और शक्ति पीठ सर्किट की भी परिकल्पना की गई है, जिसमें हस्तिनापुर, कांपिल्य, एछत्र, बरनावा, मथुरा, कौशांबी, गोंडा, लाक्षागृह जैसे स्थानों को चुना गया है। शक्तिपीठ सर्किट के अंतर्गत विंधयवासिनी देवी, अष्टभुजा से लेते हुए देवीपाटन, नैमिषारण्य, माँ ललित देवी, माँ ज्वाला देवी, शाकुंभरी देवी सहारनपुर से शिवानी देवी चित्रकूट और शीतला माता मऊ का विस्तार होगा।
- कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने बताया कि पर्यटन से जुड़ी कई गतिविधियों को जो अभी तक पर्यटन की श्रेणी में नहीं आती थीं, उन्हें भी शामिल किया गया है। इनमें बजट होटल, हैरिटेज होटल, स्टार होटल, हैरिटेज, होमस्टे, इको टूरिज़्म की इकाइयाँ कारवाँ टूरिज़्म युनिट, पिलग्रिम डॉर्मेट्री, धर्मशालाएँ, वेलनेस रिसार्ट, ऑल वेदर सीजनल कैंप, जलाशय झील, वेलनेस टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म जैसी कुल 22 एक्टिविटीज को नई नीति में स्थान मिला है।

प्रदेश के 10 ज़िलों में बनेंगे भव्य, अत्याधुनिक न्यायालय

चर्चा में क्यों ?

17 नवंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 10 ज़िलों में भव्य और अत्याधुनिक सुविधाओं वाले न्यायालय भवनों के निर्माण के लिये अधिकारियों को निर्देश दिया है।

प्रमुख बिंदु

- जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा, औरैया, हापुड़, कौशांबी, महोबा, बहराइच, चंदौली, हाथरस सहित 10 ज़िलों में नए न्यायालय भवनों के निर्माण के लिये लोक निर्माण और नियोजन विभाग के अफसरों को 15 दिन के अंदर डिटेल प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने के लिये कहा है।
- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि इन भवनों की डिज़ाइन न सिर्फ खूबसूरत हो, बल्कि इन्हें वर्टिकल आकार में बनाया जाए, जिससे भूमि की भी बचत हो। साथ ही, इन्हें आने वाले 25 से 30 साल बाद की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया जाए।
- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए न्यायालय भवनों में न्यायाधीशों के लिये सुंदर, स्वच्छ और हवादार कमरों के साथ ही अधिवक्ताओं के लिये अच्छे चैंबर, बड़ी लाइब्रेरी, कैंटीन, पार्किंग और सेमिनार हॉल भी निर्मित किये जाएँ। निर्मित किये जाने वाले नए न्यायालय भवनों को सर्व सुविधायुक्त बनाकर इन्हें प्रदेश ही नहीं, देश में भी एक मॉडल के रूप में विकसित किया जाए।
- मुख्यमंत्री ने 10 ज़िलों में नए बनने वाले न्यायालय भवनों के साथ ही न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये आवासीय कॉलोनी के निर्माण के लिये भी अधिकारियों को निर्देशित किया है। सभी न्यायालयों और रजिस्ट्रार दफ्तरों को ई-ऑफिस के रूप में अपग्रेड करने के लिये भी कहा है।
- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा है कि देश के किसी भी न्यायालय भवन में कोई भी अच्छी व्यवस्था दिखती हो तो उसे भी आर्किटेक्चर में शामिल करें। खासकर के महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के न्यायालय भवनों को ज़रूर देखें।
- उन्होंने नए न्यायालय भवनों के लिये तीन कैटेगरी बनाने के लिये कहा है, जिसमें 40-70 लाख की आबादी, 25-40 लाख की आबादी और 25 लाख से कम आबादी वाले ज़िलों के लिये अगले 25 साल की ज़रूरतों के हिसाब से न्यायालय भवनों की रूपरेखा तैयार की जाए।
- मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखने के निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने सभी ज़िलों के ज़िलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को ज़िला जज के साथ नियमित बैठक करने के भी निर्देश दिये हैं। ये बैठकें ज़िला जज की अध्यक्षता में होंगी और इसमें डीएम और एसपी अथवा एसएसपी का होना अनिवार्य है।

नोट :

उत्तर प्रदेश के प्रमुख खाद्य उत्पादों को जीआई टैग जल्द

चर्चा में क्यों ?

18 नवंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के कृषि विपणन और कृषि विदेश व्यापार विभाग ने विभिन्न ज़िलों का प्रतिनिधित्व करने वाले उत्तर प्रदेश के विशेष व्यंजनों को जीआई टैग प्रदान करने की तैयारी तेज़ कर दी है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डीएस मिश्रा के समक्ष कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार विभाग की ओर से भौगोलिक संकेतक वेबिनार में 'अतुल्य भारत की अमूल्य निधि'विषय पर प्रदेश के कृषि उत्पादों को लेकर संभावनाओं पर प्रस्तुति दी गई।
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्त्वाकांक्षी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना की शानदार सफलता के बाद, राज्य सरकार स्थानीय वस्तुओं को व्यापक मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्रमुख व्यंजनों, जैसे- मथुरा का 'पेड़ा', आगरा का 'पेठा', कानपुर का 'सत्तू'और 'बुकनू'तथा अन्य व्यंजनों पर GI टैग प्रदान करेगी।
- उत्तर प्रदेश के वाराणसी के 'चौसा आम', 'बनारसी पान'तथा 'जौनपुर की इमरती'जैसे कृषि और प्रसंस्कृत उत्पादों के लिये जीआई टैग हेतु आवेदन पहले ही प्रस्तुत किये जा चुके हैं और पंजीकरण प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
- गौरतलब है कि कृषि से जुड़े छह उत्पादों सहित राज्य के कुल 36 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। वहीं, भारत के कुल 420 उत्पाद जीआई टैग के तहत पंजीकृत हैं, जिनमें से 128 उत्पाद कृषि से संबंधित हैं।
- वर्तमान में जीआई टैग के साथ पंजीकृत उत्तर प्रदेश के छह उत्पादों में इलाहाबादी सुरखा अमरूद, मलिहाबादी दशहरी आम, गोरखपुर-बस्ती और देवीपाटन का काला नमक चावल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बासमती चावल, बागपत का रटौल आम और महोबा का देसावर पान (पान) शामिल हैं।
- करीब 15 कृषि और प्रसंस्कृत उत्पाद ऐसे हैं, जिनकी जीआई टैगिंग के लिये पंजीकरण प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है। इनमें शामिल हैं- वाराणसी का लंगड़ा आम, बुंदेलखंड का कठिया गेहूँ, प्रतापगढ़ का आँवला, वाराणसी का लाल पेड़ा, वाराणसी का लाल भरवाँ मिर्च, उत्तर प्रदेश का गौरजीत आम, वाराणसी का चिरईगाँव करोंदा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का चौंसा आम, पूर्वांचल का आदम चीनी चावल, बनारसी पान, वाराणसी की ठंडाई, जौनपुर की इमरती, मुज़फ्फरनगर का गुड़, वाराणसी की तिरंगी बर्फी और रामनगर का भांटा।
- इसके अलावा, जीआई टैगिंग के लिये जिन संभावित कृषि और प्रसंस्कृत उत्पादों का उल्लेख किया गया है, उनमें मलवां का पेड़ा, मथुरा का पेड़ा, फतेहपुर सीकरी का नमक खताई, आगरा का पेठा, अलीगढ़ की चमचम मिठाई, कानपुर नगर का सत्तू और बुकनू, प्रतापगढ़ का मुरब्बा, मैगलगंज का रसगुल्ला, संडीला का लड्डू और बलरामपुर का तिन्नी चावल शामिल हैं।
- इसके अलावा गोरखपुर का पनियाला फल, मूंगफली, गुड़-शक्कर, हाथरस का गुलाब, बिठूर का जामुन, फर्रुखाबाद का हाथी सिंगार (सब्जी), बाराबंकी का याकुटी आम, अंबेडकरनगर की हरी मिर्च, गोंडा का मक्का, सोनभद्र का सावा कोदों, बुलंदशहर का कटारिया गेहूँ, जौनपुर का मक्का, बुंदेलखंड की अरहर भी शामिल हैं।
- इस सूची में लखनऊ की रेवड़ी, सफेदा आम, सीतापुर की मूंगफली, बलिया का साठी चावल, सहारनपुर का देसी तिल और जौनपुर की मूली जैसे उत्पाद भी शामिल हैं। सरकार के प्रयासों से जल्द ही इन उत्पादों को जीआई टैग नामांकन के लिये प्रस्तावित किया जाएगा।
- जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले कृषि उत्पाद को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। जीआई टैग द्वारा कृषि उत्पादों के अनधिकृत उपयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है, क्योंकि यह किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित कृषि उत्पादों के महत्त्व को बढ़ाता है।
- जीआई टैग को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ट्रेडमार्क के रूप में माना जाता है। यह निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्थानीय आय में वृद्धि करता है और विशिष्ट कृषि उत्पादों की पहचान करके भारत के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में निर्यात और बढ़ावा देना आसान है।

नोट :

सोनौली में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा लैंडपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

20 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के महराजगंज ज़िले के डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि महराजगंज के बौद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय एक्जिट प्वाइंट सोनौली में एयरपोर्ट की तर्ज पर 120 एकड़ कैंपस में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) लैंडपोर्ट बनेगा।

प्रमुख बिंदु

- सत्येंद्र कुमार ने बताया कि लैंडपोर्ट के लिये भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। चहारदवारी का निर्माण कार्य चल रहा है। जल्दी ही शिलान्यास के बाद डीपीआर के मुताबिक कार्यदायी संस्था लैंडपोर्ट बनाएगी।
- सोनौली बॉर्डर के समीप बनने जा रहे इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बौद्ध सर्किट का एक महत्त्वपूर्ण निकास बिंदु है। यह गौतम बुद्ध की जन्मस्थली और लोकप्रिय बौद्ध पर्यटन केंद्र लुंबिनी के नज़दीक है। विदेश से आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को सोनौली में अत्याधुनिक सुविधाओं का अहसास कराने के मापदंड के आधार पर यह लैंडपोर्ट विकसित किया जाएगा।
- निर्माण के बाद कस्टम, एसएसबी, पुलिस आव्रजन सहित खुफिया एजेंसियों के कार्यालय एक ही कैंपस में रहेंगे। इससे जाँच में सहुलियत मिलेगी तथा नेपाल के साथ व्यापार में तेजी आएगी।
- लैंडपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग, नेपाल व भारत साइड पार्किंग/बस टर्मिनल, होटल, इंपेक्शन शेड कस्टम, आयात-निर्यात के लिये वेयरहाउस, रेलवे टर्मिनल में आयात-निर्यात के लिये भवन, ट्रक पार्किंग, तोरण, मेंटिनेंस शेड, हैलिपेड, क्वांरटीन ब्लॉक, आइसोलेशन ब्लॉक, वॉच टॉवर व पेट्रोल बंक आदि का निर्माण होगा।
- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने वर्ष 2004 में इंडो-नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के निर्माण की मंजूरी दी थी।

उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में बनेगा डाटा सेंटर

चर्चा में क्यों ?

21 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि राज्य के हर ज़िले में व्यूनाऊ इंफोटेक कंपनी द्वारा डाटा सेंटर के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार और व्यूनाऊ इंफोटेक कंपनी के एमडी सुखविंदर सिंह खरौर ने 13500 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमुख बिंदु

- दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश तेज़ी से ग्लोबल डाटा सेंटर ऑपरेटरों के लिये पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है और एमओयू हस्ताक्षर के बाद राज्य में एज डाटा सेंटर का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित होगा।
- उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देने के लिये राज्य में एक विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी बुनियादी ढाँचा तैयार करने के लिये कदम उठा रही है। इसी दिशा में राज्य में डाटा सेंटर स्थापित किये जाएंगे।
- कंपनी के एमडी सुखविंदर सिंह ने बतया कि व्यूनाऊ इंफोटेक कंपनी राज्य के सभी 75 ज़िलों में 750 डाटा सेंटर स्थापित करने के लिये प्रतिबद्ध है। कंपनी द्वारा पहला पायलट डाटा सेंटर मोरटा गाज़ियाबाद में पहले ही चालू कर दिया गया है।
- उल्लेखनीय है कि आईटी विभाग ने अब तक राज्य में कई हाइपरस्केल डाटा सेंटर पार्क और इकाइयाँ स्थापित करने के लिये 75,000 करोड़ रुपए निवेश को आकर्षित किया है, जिनमें से 20,000 करोड़ रुपए जून 2022 में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 के दौरान लॉन्च किये गए थे।

'उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023'

चर्चा में क्यों ?

22 नवंबर, 2022 को नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में उत्तर प्रदेश को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के संकल्प के साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 'उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023' के आयोजन की औपचारिक घोषणा की।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने ''उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023'' के लोगो का अनावरण भी किया और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज एक प्रगतिशील परिवर्तनकारी यात्रा के शिखर पर है।
- प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित 'आत्मनिर्भर भारत'का विज़न इस कायाकल्प का प्रमुख स्तंभ है। भारत को +5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का देश बनाने के प्रधानमंत्री जी के विज़न का अनुकरण करते हुए, उत्तर प्रदेश ने अपने लिये +1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार 10 से 12 फरवरी, 2023 तक लखनऊ में एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है, ताकि राज्य में उपलब्ध असीम व्यावसायिक अवसरों से देश और दुनिया लाभान्वित हो सके।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि यह इन्वेस्टर्स समिट वैश्विक औद्योगिक जगत् को आर्थिक विकास में सहयोग करने के लिये एक एकीकृत मंच प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध होगी। इस तीनदिवसीय वैश्विक सम्मेलन में विश्व स्तर के नीति-निर्धारकों, कॉर्पोरेट जगत् के शीर्ष नेतृत्व, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों, एकेडेमिया, विचार मंच एवं प्रबुद्धजनों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा तथा सामूहिक रूप से व्यावसायिक संभावनाओं एवं सहभागिता के अवसरों पर मंथन किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि समिट के भव्य आयोजन में भागीदारी करने के लिये अब तक लगभग 21 देशों ने उत्साह जताया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता करेंगे। इसके अलावा, दुनिया भर के औद्योगिक निवेशकों को समिट में आमंत्रित करने के लिये प्रदेश सरकार भी 18 देशों एवं भारत के 7 प्रमुख नगरों में रोड-शो भी आयोजित कर रही है।
- कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में सक्षम नीतिगत समर्थन एवं विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचा प्रदान करके अपने कारोबारी माहौल में बड़े पैमाने पर सुधार किया है। प्रोएक्टिव इनवेस्टर कनेक्ट तथा हैंडहोल्डिंग के लिये समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने एवं उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिये 'निवेश सारथी'नामक एक नई ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है। इसके अलावा एक ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम भी विकसित किया गया है।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य की विभिन्न सेक्टोरल नीतियों तथा राज्य में निवेश की संभावनाओं पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया।

उत्तर प्रदेश के शहरों में लागू होगा इंदौर का SWM मॉडल

चर्चा में क्यों ?

23 नवंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्वच्छ, हरित और नियोजित शहरों को सुनिश्चित करने के लिये, राज्य सरकार राज्य के शहरी निकायों में इंदौर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) मॉडल को लागू करेगी।

प्रमुख बिंदु

- देश के सबसे स्वच्छ शहर माने जाने वाले इंदौर के स्वच्छता मॉडल की व्यापक समीक्षा के लिये उत्तर प्रदेश की एक टीम ने हाल ही में अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान इंदौर शहर की रणनीति का आकलन किया और ट्रेंचिंग ग्राउंड में स्थित एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का अवलोकन भी किया।
- उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक नेहा शर्मा सहित मथुरा-वृंदावन, झाँसी, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, फर्रुखाबाद, कुशीनगर, इकदिल नगर, मुरादाबाद, गोरखपुर जैसे नगरीय निकायों के करीब 13 प्रतिनिधि दौरे पर गए थे।
- उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को इंदौर शहर में स्पॉट फाइन और कचरा संग्रहण शुल्क के बारे में जानकारी दी गई। यात्रा के दौरान पिछले छह वर्षों में स्वच्छता के लिये की गई पहलों पर एक प्रस्तुति दी गई।
- इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के अध्यक्ष आदर्श गोयल और दो अन्य सदस्यों ने भी ट्रेंचिंग ग्राउंड स्थित बायो सीएनजी प्लांट का दौरा किया और प्लांट की कार्यप्रणाली को समझा।
- उत्तर प्रदेश के शहरों में नगर निकायों के माध्यम से 300 टन से 400 टन गीले कचरे से बायो सीएनजी प्लांट तैयार करने की योजना है।

नोट :

गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित होगा इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि गोरखपुर के कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में कंसोरिटियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर (जीसीआईएआर) स्थापित होगा।

प्रमुख बिंदु

- गोरखपुर के कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में कंसोरिटियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर (जीसीआईएआर) स्थापित होने से पूर्वांचल में गेहूँ, मक्का एवं धान की उन्नत किस्म के बीजों का विकास होगा और साथ ही विद्यार्थियों को शोध क्षेत्र में व्यापक अनुभव होगा।
- कुलपति प्रो. राजेश सिंह ने बताया कि रिसर्च सेंटर में गेहूँ, मक्का एवं धान की प्रगतिशील किस्मों के विकास से किसानों की आय को दोगुना करने में सहयोग मिलेगा।

एमएनएनआईटी ने बनाई भारत की पहली मानव रहित कार

चर्चा में क्यों ?

25 नवंबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित मोती लाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एमएनएनआईटी) के बीटेक के छात्रों ने भारत की पहली मानव रहित कार बनाई है। पहले चरण में परीक्षण सफल होने के बाद 27 नवंबर को माइक्रोसाफ्ट एशिया के अध्यक्ष अहमद मजहरी के सामने इसका पहला डेमो होगा।

प्रमुख बिंदु

- एमएनएनआईटी के 1995 बैच के अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार ने बताया कि बिना ड्राइवर के चलने वाली पहली मानव रहित कार के प्रोजेक्ट का पहला चरण दो साल की अथक मेहनत के बाद पूरा कर लिया गया है। प्रयोग के तौर पर गोल्फ कार्ट में इस कार के सिस्टम को फिट किया गया है। कोडिंग और प्रोग्रामिंग सफल होने के बाद फिलहाल इस कार को किसी भी सड़क पर सीधे चलने के लिये उतारा गया है।
- इस कार के आगे और पीछे कैमरा लगाया गया है, जिससे यह कार बिना किसी मानव चालक के ही सड़क पर स्वत: चल सकेगी। कार को सामने से आने वाली कोई भी गाड़ी, आदमी, भीड़, जानवर या फिर गड्डा, कटान सब कुछ दिख जाएगा और किसी तरह का अवरोध होने पर वह अपने आप ब्रेक लगाकर रुक जाएगी।
- इसके अलावा अवरोधक के हटने के साथ ही यह मानव रहित कार अपने गंतव्य के लिये रवाना भी हो जाएगी। वह सड़क दुर्घटना के हर कारणों को भाँप सकेगी। फिलहाल यह कार अभी सीधे रास्ते पर ही चल सकेगी।
- महीने भर बाद दूसरा चरण पूरा होने पर वह किसी भी मोड़ या घुमावदार रास्ते पर चलने के साथ ही आगे पीछे मुड़कर फर्राटा भर सकेगी। इसके बाद कोडिंग के आधार पर यह कार किसी भी लोकेशन पर बिना किसी चालक के ही पहुँचने में सक्षम हो जाएगी।
- बीटेक छात्र विभांशु समेत सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर के कुल 19 छात्रों ने मिलकर इस कार को तैयार किया है।
- एमएनएनआई के 1995 बैच के छात्र रहे आरआरडी गो क्रिएटिव के वाइस प्रेसीडेंट रोहित गर्ग के अलावा सड़क एवं परिवहन मंत्रालय नई दिल्ली में अधीक्षण अभियंता के पद पर तैनात राजेश कुमार ने इस मानव रहित कार के निर्माण के लिये मार्गदर्शन किया और फंडिंग भी की है। इस कार के निर्माण पर सात लाख रुपए की लागत आई है।

मुख्यमंत्री ने रामनगरी अयोध्या में 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया

चर्चा में क्यों ?

27 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी अयोध्या में परंपरागत तरीके से होने वाले 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया। यह मेला 30 नवंबर, 2022 तक चलेगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण मेले के द्वितीय दिवस के कार्यक्रम पोस्टर (आवरण छवि) का लोकार्पण भी किया।
- भारत के सांस्कृतिक व आध्यात्मिक वैभव की पुनर्स्थापना के लिये उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सदस्यों के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है।
- रामायण मेला समिति के संयोजक आशीष कुमार मिश्र ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस पोस्टर का लोकार्पण किया है, उसमें रामायण मेला में होने वाले द्वितीय दिवस के कार्यक्रम के क्रम में राम बारात आगमन, पाँव पूजन की रस्म, चारों भाइयों का अग्नि का फेरा और सभी वर-वधु का ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त करने की लीला को दर्शाया गया है।
- इस आवरण छवि को उकेरने का कार्य वैष्णवी गुप्ता एवं प्रिया गुप्ता ने किया है। आवरण छवि में भारतीय लोक कला पर आधारित अवध की लोककला को प्रदर्शित किया गया है। इससे पहले पहला पोस्टर श्री राम जन्मभूमि के गर्भगृह से लोकार्पित किया गया था।
- गौरतलब है कि अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत 1982 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की थी। उन्होंने उद्घाटन सत्र में ही राम की पैड़ी प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। पहले रामायण मेला में लगातार चार दिन मंत्रियों ने अलग-अलग विकास योजनाओं का ऐलान किया, जो इस समय की विकास योजनाओं में प्रमुख हैं।
- पहले रामायण मेला में ही परिक्रमा मार्ग को पक्का करवाने, सरयू तट का नया घाट से लेकर गुप्तारघाट तक विस्तार व सांस्कृतिक विकास के लिये राम कथा पार्क के निर्माण की घोषणा कर उन पर काम शुरू किया गया था।
- 1980 के दशक में रामायण मेला का आकर्षण चरम पर रहा। इसी मेला में श्रीलंका, कोरिया, मलेशिया सहित कई देशों की रामलीला का मंचन किया गया, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं।

वाराणसी एयरपोर्ट पर जल्द शुरू होगी डिजी यात्रा

चर्चा में क्यों ?

29 नवंबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी एयरपोर्ट निदेशक अर्यमा सान्याल ने बताया कि वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर 1 दिसंबर से डिजी यात्रा की सेवा मिलने लगेगी। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली से इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि डिजी यात्रा के तहत यात्रियों के लिये उनका चेहरा ही बोर्डिंग पास होगा। इससे यात्रियों को तमाम कागज़ात से छुटकारा मिलेगा और उनके समय की बचत होगी।
- पहले घरेलू विमानों पर इस डिजी यात्रा के तहत प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिये डिजी यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इससे बोर्डिंग पास के दौरान लगने वाले समय में 50 फीसदी की बचत होगी।
- उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर यात्री मोबाइल से भी डिजी यात्रा के लिये पंजीकरण करा सकते हैं। एयरपोर्ट पर लगे डिजी यात्रा क्यूआर कोड को मोबाइल से स्कैन किया जाएगा। इसके बाद पंजीकरण के लिये आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर ज़रूरी होगा। डिजी यात्रा के लिये प्ले स्टोर से डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड कर यात्री घर-बैठे भी पंजीकरण कर सकते हैं। इससे यात्रियों के समय की बचत के साथ उन्हें आसानी से टर्मिनल भवन में प्रवेश मिलेगा।
- इसके अलावा डिजी यात्रा के दौरान एयरपोर्ट पर लगी मशीन में यात्री का बेसिक डाटा स्टोर हो जाएगा। इसके बाद जब भी यात्रा करना होगा, उसे किसी भी तरह के कागज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यात्री एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा मशीन में अपना चेहरा व टिकट स्कैन करा कर प्रवेश कर सकेंगे। एक दिसंबर को डिजी यात्रा के जरिये प्रवेश पाने वाले यात्री को विशेष इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा अन्य यात्रियों को भी उपहार दिया जाएगा।
- अर्यमा सान्याल ने बताया कि एयरपोर्ट के गेट नंबर दो पर ही डिजी यात्रा की सुविधा होगी। डिजी यात्रियों के लगेज के लिये अलग काउंटर होगा। इन यात्रियों के लगेज संबंधित काउंटर से विमान तक पहुँचा दिये जाएंगे।

नोट :

- शुरूआत में इंडिगो एयरलाइंस यह सेवा देगी। पहले दिन दिल्ली के विमान यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इसके बाद एयर इंडिया और विस्तारा सेवा देंगी। अभी वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो से यात्रा करने वाले यात्रियों को ही डिजी यात्रा की सुविधा मिल रही है।
- उल्लेखनीय है कि वाराणसी एयरपोर्ट पर 1 दिसंबर से डिजी यात्रा की शुरुआत हो रही है। इससे पहले डिजी यात्रा का ट्रायल किया जा रहा था। एयरपोर्ट पर जनवरी से डिजी यात्रा के लिये ट्रायल शुरू हुआ था, तब से अभी तक 5526 यात्रियों ने डिजी यात्रा के तहत यात्रा की है। वहीं 877 यात्रियों ने ऐप डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन किया है।
- वाराणसी के साथ ही दिल्ली और बंगलूरू एयरपोर्ट पर भी डिजी यात्रा का शुभारंभ होगा। हालाँकि, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट (बाबतपुर हवाई अड्डा) देश का पहला हवाई अड्डा होगा, जहाँ सेवाएँ एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधीन संचालित हैं।

दृष्टि The Vision

नोट :